क्षेत्र के कारखानों के प्रबंध को लोकतांत्रिक बनाया जाए ताकि उनके प्रबंध में कामगार भी पूरी तरह भागीदार हो सकें।

(3) एल्यूमिनियम की दोहरी मूल्य-निर्धारण नीति समाप्त की जाए ।

(4) एल्यूमिनियम उद्योग के मजूरी ढांचे में सुधार किया जाए और उसे इस्पात उद्योग के अनुरूप बनाया जाए। इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा प्रबंधकों और कामगारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई जाए।

(5) बिजली सप्लाई की कटौती के कारण उत्पादन में कमी होने पर कामगारों को प्रोत्साहनों सहित पूरी मजूरी की गारण्टी दी जाए ।

सरकार की क्रम-वार प्रतिक्रिया इस प्रकार :---

(1) सरकार ने हिंडालको के ग्रहीत बिजली घर के विस्तार की मंजूरी दे दी है । अन्य एल्यूमिनियम उत्पादकों से ग्रहीत बिजली-घरों की स्थापना हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र मे प्रस्तावित एल्यूमिनियम कम्पलैक्स की योजना मे एक ग्रहीत बिजली घर का प्रावधान है ।

(2) परिस्थितियोंवश जरूरत होने पर एल्यूमिनियम कारखानों के राष्ट्रीयकरण पर विचार किया जाएगा । कारखाना-प्रबंध मे श्रमिकों की भागीदारी के बारे में सरकार द्वारा किए गए नीति संबंधी निर्णय को एल्यूमिनियम उद्योग पर भी लागू किया जाएगा।

(3) एल्यूमिनियम की दोहरी मूल्य नीति अक्तूबर, 1978 से समाप्त कर दी गई है ।

(4) और (5) चूंकि यह उद्योग सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में है और अधिकतर उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में होता है तथा कंपनियां, भिन्न-भिन्न वित्तीय क्षमताओं सहित, काफी भिन्न हालतों में काम करती हैं, इसलिए इन सुझावों को स्वीकार करना या कार्यान्वित करना संभव नहीं है ।

वर्तमान कर प्रणाली का पुनरीक्षण

773. **श्री रामावतार शास्त्री:**

श्री पीयूष तिरकी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्तमान कर प्रणाली का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बरोट): (क) सरकार, कर पद्धति की सतत समीक्षा करती रहती है ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

भारत के साथ उद्योग और व्यापार सहयोग के विस्तार के लिए पैकेज कार्यक्रम के संबंध में फ्रांस का प्रस्ताव

774. **श्री नन्द किशोर शर्मा:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस सरकार ने भारत के साथ उद्योग और व्यापार सहयोग के विस्तार के लिए पैकेज कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) क्या भारत सरकार इस कार्यक्रम के बारे में विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की आशा है?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ). फ्रांसीसी सरकार ने औद्योगिक और व्यापार सहयोग के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों की पेशकश की है । संबंधत मंत्रालय/विभाग इन प्रस्तावों की

जांच कर रहे हैं/उन पर विचार कर रहे हैं:---

1. फ्रांसीसी सरकार की सहायता से उड़ीसा में अल्मीनियम काम्पलेक्स की स्थापना/फ्रांसीसी सरकार ने भारत सरकार को व्यापक वित्तीय सुविधाएं देने की पेशकश की है। खान विभाग/आर्थिक विभाग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

2. फ्रांस की सहायता से नन्दीरा और गीडी-ए खानों के विकास के लिए फ्रांस ने विशिष्ट प्रस्ताव की पेशकश की है। कोल इंडिया लमटेड और कोयला वभाग उस प्रस्ताव पर वचार कर रहे हैं जसमें विस्तृत सम्भाव्यता रिपेटों का तैयार किया जाना और परियोजना के लिए वित्तीय सुविधाओं को अन्तिम रूप दिया जाना शामिल है ।

3. कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, जिसमें राजस्थान नहर, बुन्देलखंड, केरल के बांये किनारे से संबंधित एकीकृत विकास परियोजनाएं शामिल हैं, सहयोग के लिए फ्रांस के प्रस्ताव पर कृषि मंत्रालय फ्रांस की और आगे प्रतिक्रिया के बारे में प्रतीक्षा कर रहा है।

4. फ्रांस ने इलैक्ट्रोनिक स्पिचिंग के क्षेत्र में सहयोग के प्रस्तावों की पेशकश की और हाल ही में उसने 5,00,000 लाइनों के कारखाने की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव की पेशकश की है। संचार मंत्रालय उन पर विचार कर रहा है।

5. टेलीटैक्स सिस्टम एन्टीओप के और भारतीय टी. वी. व्यवस्था को रंगीन बनाने की सम्भाव्यता के लिए एस. ई. सी. ए. एम. प्रणाली के भारत में प्रदर्शन के लिए फ्रांस के प्रस्ताव पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय विचार कर रहा है।

6. फ्रांस ने बल्ब टाइप जल विद्युत एककों के क्षेत्र सहयोग का प्रस्ताव किया हाल ही में ज्वार बिजली उत्पादन के क्षेत्र में फ्रांस को सहायता को सहयोग के एक सम्भाव्य क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

7. नवीकरण योग्य ऊर्जा के क्षेत्र में खास तौर से सौ पम्प टर्बाइनों जैसे उपस्कर के तथा सौर तापीय प्रयोग के लिए सहायक उपस्करों के आदान प्रदान के संबंध में फ्रांस के प्रस्ताव के संदर्भ में विचार विमर्श हुआ है।

8. भारी उद्योग विभाग को फ्रांस से मोटर गाड़ियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इसका पुनरीक्षणा उस विभाग द्वारा किया जाएगा। हाल ही में मैसर्ज महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा की जीपों में लगाए जाने के लिए डीजल इंजनों के उत्पादन के लिए उस फर्म को फ्रांस के मैसर्ज पिगोट के साथ सहयोग करने की अनुमति दी गई है।

भारत और बुल्गारिया के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग का विकास

775. **श्री नन्द किशोर शर्मा:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके तथा बुल्गारिया के मंत्री के बीच हाल ही की बातचीत में भारत और बुल्गारिया के बीच दीर्घावधि आधार पर व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के विकास के सम्बन्ध में बातचीत की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) तथा (ख). 22 अप्रैल, 1980 को बुल्गारिया विदेश व्यापार के प्रथम उप मंत्री से दीर्घावधि आधार पर भारत-बुल्गारिया व्यापार तथा वाणिज्यिक सम्बन्धों के विस्तार तथा विविधीकरण के बारे में सामान्य बातचीत की। उन्होंने, विशेषरूप से भारत अर्थ मूवर्स द्वारा उत्पादित अर्थ मूविंग उपस्कर तथा भारत से लोह अयस्क की पर्याप्त मात्रा में खरीदारी करने में अपने देश की तीव्र रूचि दर्शाई। यह बात भी उनके ध्यान में लाई गई कि चूंकि भारत ने एक व्यापक औद्योगिक आधार विकसित कर लिया है इसलिए यह बुल्गारिया को मशीनी औजार, मेटल वर्किंग मशीनें, इलैक्ट्रानिक संघटक तथा उपस्कर और अन्य विभिन्न इंजीनियरी मदों जैसे जटिल उत्पाद भी सप्लाई कर सकता है।